



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 7858 वर्ष 2026

लाल बिहारी यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम आशीष यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता है। उसने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, तहसीलदार, तहसील मढ़ियाहू, जिला जौनपुर को भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत मामला संख्या आरएसटी/4385/2024, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202414360604385 (ग्राम सभा बनाम राजाराम) का निर्धारित समय के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. जब न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रश्न उठाया, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

3. इसके अलावा, पूरी रिट याचिका में न तो कुछ कहा गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत कैसे आता है। वैसे भी, संपूर्ण याचिका का अवलोकन करने और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बात सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

4. पीड़ित पक्ष के पक्ष में किसी अधिकार का अस्तित्व रिट याचिका दायर करने का आधार प्रदान करता है, जैसा कि **विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2001) 4 एससीसी 734** में कहा गया है:-

“2. सामान्यतः, किसी व्यक्ति को रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह विवादित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है, या उसके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से उल्लंघन नहीं हुआ है, और न ही ऐसे अधिकारों के उल्लंघन का कोई तत्काल खतरा है, या लागू नियमों की अनदेखी करते हुए उसके अर्जित हितों का उल्लंघन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत, अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में मौजूद अधिकार पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवाद केवल उन मामलों में है जहां दायर की गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। -कॉर्पस या क्वो वारंटो या जनहित में दायर किया गया। यह विवेक का विषय है कि न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उन मामलों तक सीमित रखे जहां किसी विशिष्ट व्यक्ति या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और किसी तीसरे पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से किए गए गलत कार्य या चोट के मामलों पर विचार न करे, जहां एक प्रभावी कानूनी सहायता संगठन मौजूद हो जो ऐसे मामलों की देखभाल कर सके। यहां तक कि जनहित में दायर किए गए मामलों में भी, न्यायालय किसी तीसरे पक्ष द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि कानूनी गलत कार्य, कानूनी चोट या अवैध बोझ का खतरा है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारित वर्ग, गरीबी, असहायता, अक्षमता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण, राहत के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है।”

5. इसी प्रकार, अयाउबखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2013) 4 एससीसी 465 में रिपोर्ट किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित पक्षों के प्रवर्तनीय अधिकारों का अस्तित्व, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की पूर्व शर्त है।

“9. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि किसी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह प्राधिकारी/न्यायालय को यह संतुष्ट न कर दे कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। केवल वही व्यक्ति जिसने कानूनी चोट का सामना किया है या कर रहा है, वह किसी कार्य/आदेश आदि को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका या तो किसी वैधानिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से, या जब अपीलकर्ता द्वारा यह शिकायत की जाती है कि अधिकारियों द्वारा वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, तब विचारणीय है। इसलिए, प्रवर्तन के लिए न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार

उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय, निश्चित रूप से, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक कर्तव्य के पालन को लागू कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उसे आग्रह करने का कानूनी अधिकार है। इस प्रकार के प्रदर्शन पर। ऐसे अधिकार का अस्तित्व अदालतों के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त है। ऐसे असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह निहित है कि मांगी गई राहत किसी कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसे अधिकार का अस्तित्व ही न्यायालय द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग का आधार है। जिस कानूनी अधिकार को लागू किया जा सकता है, वह सामान्यतः अपीलकर्ता का अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी संबंध में राहत के लिए न्यायालय में आता है। [देखें राज्य] उड़ीसा बनाम मदन गोपाल रंगटा [एआईआर 1952 एससी 12], सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1954 एससी 728], कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एआईआर 1962 एससी 1044], राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 5 एससी 460 : एआईआर 1996 एससी 2736] और तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक शेयरधारक कल्याण एसोसिएशन (2) बनाम एस.सी. शेखर [(2009) 2 एससीसी 784]।

10. "कानूनी अधिकार" से तात्पर्य कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाले हक से है। इस प्रकार, इसे कानून के नियम द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए लाभ या सुविधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। "पीड़ित व्यक्ति" अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है; इसलिए, पीड़ित व्यक्ति अनिवार्य रूप से वह होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित या खतरे में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पड़ गया हो। (देखें शांति कुमार आर. कांजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क [(1974) 2 एससीसी 387 : एआईआर 1974 एससी 1719] और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) 3 एससीसी 592 : एआईआर 1977 एससी 1361]।)

11. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय [(2008) 5 एससीसी 217: एआईआर 2008 एससी 1289] में, इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि, यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे चुनाव या अन्य व्यक्तियों के चयन के संबंध में पीड़ित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।”

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद के मामले में, जो 1976 (1) एससीसी 671 में प्रकाशित हुआ था, यह निर्णय दिया कि कोई अजनबी, जो पीड़ित व्यक्ति नहीं है, न तो सर्टिओरारी और न ही मेंडमस के लिए रिट दायर कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिया गया है:-

“50. यद्यपि एक कठोर दृष्टिकोण से बचना चाहिए, फिर भी, नियम के अनुसार, न्यायालय को किसी “अजनबी” के कहने पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि गंभीर न्याय उल्लंघन से जुड़ी कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जिसका सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता एक “अजनबी” है, न कि कोई हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति, तो भी वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जो उसके कहने पर सर्टिओरारी याचिका जारी करने को उचित ठहराए। इसके विपरीत, इन विवेकाधीन शक्तियों का उसके पक्ष में प्रयोग करने का परिणाम, कुल मिलाकर, सार्वजनिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नीति के विरुद्ध होगा। यह इस व्यवसाय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा, जो व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है; यह अपीलकर्ता के सिनेमा के एकाधिकार को कायम रखने की प्रवृत्ति रखेगा। शहर में व्यापार; और सबसे बढ़कर, यह वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत प्राप्त हैं, जिसके तहत वे "कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों" के अधीन व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं।"

7. प्यारे लाल और अन्य बनाम उप निदेशक, कंसोलिडेशन मैनुपुरी और अन्य के मामले में, जिसका उल्लेख 2005 एएलएल एल. जे. 1966 में हुआ है, पैरा-7 में यह कहा गया है कि:-

"पीड़ित शब्द का शब्दकोश अर्थ है 'हानि या चोट झेलना'। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, पीड़ित पक्ष/व्यक्ति वह है जिसका कानूनी अधिकार किसी शिकायत किए गए कार्य से आहत हुआ हो, या जिसका आर्थिक हित किसी आदेश या निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हो। पीड़ित शब्द किसी गंभीर शिकायत, किसी व्यक्तिगत या संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित होने, या किसी पक्ष पर बोझ या दायित्व थोपे जाने को संदर्भित करता है।" कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम खंड IV 356 (प्रथम संस्करण) के अनुसार, किसी पक्ष या व्यक्ति को किसी निर्णय से पीड़ित तभी कहा जा सकता है जब वह निर्णय उसके व्यक्तिगत, आर्थिक या संपत्ति संबंधी अधिकारों पर प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभाव डालता हो।

8. इस स्थिति में, चूंकि याचिकाकर्ता "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसकी ओर से दायर की गई यह रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है।

9. यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

18 मार्च 2026

स्वाति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।